

पिछड़े वर्ग के छात्रों की शिक्षा स्थिति का अध्ययन

Ragini Bala^{1*}, Dr. Yuti Singh²

¹ Research Scholar, School of Education

² Associate Professor, Sardar Patel University, Balaghat, MP

सार - बिहार में पिछड़े वर्गों की वर्तमान शिक्षा प्रणाली, विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा संचालित, अपने छात्रों को वर्तमान जटिल सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्रदान नहीं कर सकती। शिक्षण सहायक सामग्री की कमी, अपर्याप्त व्यावहारिक रूप से योग्य शिक्षक, और कुछ महत्वपूर्ण विषयों की लापरवाही और पर्याप्त शैक्षिक बुनियादी ढांचे की कमी हमारी अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी को एक आवश्यक सीमा तक बनाने में विफल रहती है जो अंततः गरीबी बेरोजगारी समस्या के कारकों में से एक के रूप में कार्य करती है। इसलिए आधुनिक प्रतिस्पर्धी और तकनीकी दुनिया के बराबर होने के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली को कुछ हद तक बदला जाना चाहिए। मौजूदा समस्याओं की पहचान की जानी चाहिए और तदनुसार, इन समस्याओं को हल करने के लिए उचित रणनीति बनाई जानी चाहिए।

मुख्यशब्द - प्रतियोगिता; शिक्षा; शैक्षिक अवसरचना; प्रभाव और रणनीति।

-----X-----

प्रस्तावना

किसी राष्ट्र का बहुआयामी विकास ज्ञानवान, गतिशील, संवेदनशील और रचनात्मक मानव संसाधनों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इन मानव संसाधनों की उपस्थिति सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है और मानव प्रयास के हर क्षेत्र में देश को गुणात्मक रूप से चमकाने में सक्षम बनाती है। यह शिक्षा है जो सभी को विकास के फल प्रदान करके इक्विटी के साथ सतत विकास को बनाए रखने में मदद करते हुए परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जावान मानव संसाधनों का उत्पादन करने में मदद करता है। शिक्षा एक सक्रिय लोकतंत्र का आधार है जिसमें शिक्षित नागरिक राष्ट्र के आंतरिक विकास और विश्व समुदाय में इसकी रचनात्मक भूमिका का समर्थन करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। यह जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उत्पादकता, आय और रोजगार के अवसरों के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास, अनुप्रयोग और अनुकूलन का समर्थन करता है। शिक्षा में सुधार से न केवल दक्षता बढ़ाने की उम्मीद की जाती है, बल्कि जीवन की समग्र गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। यह शिक्षा है जो आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता और मजबूत सामाजिक सामंजस्य के साथ-साथ असमानता को कम करने और गरीबी को कम करने में योगदान करती है। यह बुनियादी और साथ ही

विशिष्ट कौशल प्रदान करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है जो उत्पादकता और उच्च प्रति व्यक्ति आय सुनिश्चित करता है। तो, शिक्षा राष्ट्रीय समृद्धि और कल्याण की कुंजी है। यह काम, उत्पादकता और आर्थिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ज्ञान और तकनीकी कौशल के साथ व्यक्ति को लैस करता है। शिक्षा व्यक्तिगत विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रभावशीलता को बढ़ाती है, जो एक प्रतिस्पर्धी समाज में सफलता के लिए आवश्यक हैं। इसलिए, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज अपने संचित मूल्यों, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और रीति-रिवाजों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है और प्रभावित करता है कि कैसे एक व्यक्ति सोचता है, महसूस करता है और कार्य करता है।

साहित्य की समीक्षा

राघवेंद्र और नारायण (2014) ने भारत में प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में हुई प्रगति और प्राथमिक शिक्षा (यूईई) के एकरूपकरण को प्राप्त करने में आ रही समस्याओं का अवलोकन किया। उन्होंने सरकार द्वारा शुरू की गई नीति, संस्थागत और कार्यक्रम प्रयासों की समीक्षा की और अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों और साक्षरता उपलब्धियों में सामान्य आबादी के संबंध में लगातार ग्रामीण-शहरी

असमानताओं, लिंग अंतर, अंतर और अंतर राज्य विविधताओं पर प्रकाश डाला।

मित्रा एट अल। (2018) ने उत्तर प्रदेश, भारत के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर रिमोटनेस यानी स्कूल, सड़क और रेल कनेक्टिविटी के स्थान का अध्ययन किया। यह बताया गया कि दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की खराब गुणवत्ता के लिए शिक्षक प्रवास और प्रवास की इच्छा सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

प्रेमकुमार और अहमद (2010) ने समावेशी विकास नीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कर्नाटक के शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं का अध्ययन किया। यह पाया गया कि गुलबर्गा शैक्षिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है, जो हाई स्कूल ड्रॉप-आउट दर और कम साक्षरता दर द्वारा इंगित अन्य क्षेत्रों की तुलना में है। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं ने स्कूल नामांकन में वृद्धि की है, लेकिन उच्च विद्यालय ड्रॉप-आउट दर के कारण छात्र अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा किए गए ग्रेड थर्ड के छात्रों के परीक्षण से पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर, पांच में से एक छात्र मूल भाषा की परीक्षा में फेल हो गया और एक तिहाई गणित की परीक्षा में फेल हो गए। औसत परिणाम विभिन्न राज्यों में और छत्तीसगढ़ में काफी भिन्न हैं, अधिकांश छात्रों ने गणित और रीडिंग टेस्ट दोनों में असफल रहे। ग्रामीण छात्रों की निचली उपलब्धि की पुष्टि अन्य सर्वेक्षणों से भी होती है। पांचवीं कक्षा के लगभग आधे छात्रों में दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए एक पाठ पढ़ने की क्षमता होती है। इसी तरह, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में छात्रों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि चौथे और पांचवीं कक्षा के अधिकांश छात्रों ने गणित और साक्षरता में कई विकल्प परीक्षण विफल कर दिए जो चौथे ग्रेड के लिए डिज़ाइन किए गए थे। इस प्रकार, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की खराब गुणवत्ता की ओर इशारा करते हुए।

सिंह (2012) ने दो अनूठे और नए सूचकांकों का उपयोग किया, अर्थात् इनपैरिटी ऑफ इंडेक्सिटी इंडेक्स (IOI) और ह्यूमन ऑपर्युनिटी इंडेक्स (HOI) जिसका उपयोग अवसर की असमानता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। भारतीय बच्चों के बीच प्राथमिक शिक्षा के लिए अवसर की असमानता को मापने के लिए एक व्यक्ति का नियंत्रण)। परिणाम स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच में काफी क्षेत्रीय विविधताओं का सुझाव देते हैं।

कुमार और सिंगला (2013) ने प्रमुख भारतीय राज्यों में आर्थिक प्रदर्शन के पैटर्न का निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय अंतर-राज्य असमानताओं का विश्लेषण किया। उन्होंने पूर्व सुधार अवधि (1980-81) की तुलना में पिछले सुधार की अवधि (2010-11) के

दौरान साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, विकास दर, मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) और विकास व्यय में सुधार की सूचना दी, हालांकि इन संकेतकों में अंतर असमानताएं बहीं।

अग्रवाल (2014) ने भारत में 1993 और 2009 के बीच शैक्षिक प्राप्ति दर और शैक्षिक असमानता का अध्ययन किया। 2009 में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में देश की लगभग ३२% आबादी निरक्षर थी और केवल उच्च शिक्षा प्राप्त की है। राज्य के अलावा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की शैक्षिक उपलब्धि में उल्लेखनीय असमानता है। हालांकि 1993 और 2009 के बीच असमानता में 14 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन असमानता की सीमा उच्च बनी हुई है (2009 में 50% से ऊपर)। वर्ष 2009 में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय विपरीत सूचकांक 18% अधिक है। आंध्र प्रदेश राज्य में 6-13 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का गैर-नामांकन अध्ययन किया गया था। यह पता चला कि माता-पिता गैर-उपयुक्त स्कूल समय, स्कूल में उचित बुनियादी ढांचे की कमी, कम आर्थिक स्थिति, घरेलू कामों, अलग-अलग लड़कियों के स्कूल की अनुपस्थिति और स्कूल में महिला शिक्षकों की कमी के कुछ प्रमुख कारकों या कम नामांकन के कारणों के रूप में देखते हैं। हालांकि समुदाय के नेताओं के अनुसार गैर-नामांकन के कारण माता-पिता की गरीबी और उनकी भावना थी कि शिक्षा जीवन की जरूरतों को पूरा करने में मदद नहीं करेगी।

यादव (2018) के अनुसार, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों में स्कूल ड्रॉप-आउट के लिए शिक्षकों द्वारा दिए गए प्रमुख कारणों में घरेलू और कृषि कार्य में छात्रों की भागीदारी, माता-पिता की कम साक्षरता दर, छात्रों में रुचि की कमी, व्यापक छात्र-कक्षा अनुपात शामिल थे। और भारी पाठ्यक्रम आदि, छात्रों के अनुसार, शिक्षकों द्वारा दंड, शिक्षण में पाठ्य-पुस्तकों के बजाय हेल्प-बुकस का उपयोग, शिक्षा के मूल्य की अभिभावक अज्ञानता और लड़कियों के लिए घरेलू काम की प्राथमिकता स्कूल के खराब प्रदर्शन के महत्वपूर्ण कारण हैं। अभिभावकों के अनुसार, सह-शिक्षा विद्यालय, शिक्षकों के हित में कमी और प्रगति रिपोर्ट न मिलना प्रमुख अपराधी हैं। एक पूरे निष्कर्ष के रूप में दृढ़ता से संकेत मिलता है कि परिदृश्यों में राज्यों का खुलासा हो रहा है, खासकर आबादी के वंचित वर्ग की जेब में सूक्ष्म स्तर पर निस्संदेह निराशाजनक है अगर पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है।

बिहार के सभी स्कूलों में पिछड़े वर्ग के छात्र

अगले शैक्षणिक वर्ष से, बिहार के सभी स्कूलों में कुलीन वर्ग सहित छह से चौदह वर्ष की आयु के आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें अलग रखनी होंगी। इसके लिए

प्रावधान को शिक्षा का अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य करता है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच

इस प्रकार किया गया आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करेगा, जो कभी उनमें से कई के लिए एक सपना था। कई विकासशील देशों की तुलना में भारत में साक्षरता का स्तर बहुत कम है और सबसे बुरी बात यह है कि देश में उनमें से कई के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा वहनीय नहीं है। तो यह उस दिशा में एक अनुकूल कदम है और समय की मांग है। यह प्रत्येक छात्र को उनकी वित्तीय पृष्ठभूमि के बावजूद समान अवसर सुनिश्चित करेगा।

शैक्षिक संस्थानों में अपर्याप्त शिक्षक और कक्षा

एक शैक्षणिक संस्थान को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पर्याप्त और योग्य शिक्षक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में, प्रत्येक शिक्षक को अद्यतन किया जाना चाहिए। केवल आदिम व्याख्यान पद्धति, विशेष रूप से प्राथमिक और उच्च विद्यालय स्तर पर, बच्चों को पर्याप्त सामग्री की आपूर्ति नहीं कर सकती है। निचली कक्षाओं में केवल व्याख्यान पद्धति से ड्रॉपआउट दर बढ़ जाती है। क्योंकि यह छात्रों के लिए कक्षाओं को उबाऊ बनाता है और यह सुनिश्चित है कि ड्रॉपआउट के बच्चे गरीब परिवार की पृष्ठभूमि के हैं। इसलिए कक्षा को रोचक बनाने के लिए पर्याप्त शिक्षण सहायक सामग्री और आधुनिक तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, स्कूल के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त शिक्षक की आवश्यकता है। लेकिन, अगर हम बिहार के इस परिदृश्य को देखने जा रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से इससे नाखुश होंगे। आइए हम बिहार में विशेष रूप से निचली कक्षाओं में शिक्षक संकट का विश्लेषण करें।

गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि और शिक्षण नौकरियों के छात्र

एक निश्चित औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद लोग रोजगार की उम्मीद करते हैं। कम विकसित देशों में अधिकांश लोग (विशेषकर गरीब) अपने आंतरिक गैर-आर्थिक लाभों के लिए शिक्षा की मांग नहीं करते हैं, बल्कि केवल इसलिए कि यह आधुनिक क्षेत्र में रोजगार हासिल करने का एकमात्र साधन है। इसलिए, गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए रोजगार अंतिम गंतव्य है। लेकिन, रोजगार किसी राज्य या राष्ट्र की नौकरी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। बिहार जैसा राज्य औद्योगिक रूप से विकसित नहीं है, इसलिए लोग मुख्य रूप से सरकारी नौकरी पाने के लिए सेवा क्षेत्र पर निर्भर हैं। शिक्षा क्षेत्र

बिहार की तरह राज्य में सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। लेकिन यहां एक सवाल यह उठता है कि क्या शिक्षा क्षेत्र गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों को अवशोषित कर रहा है या नहीं।

पिछड़े वर्गों की शिक्षा की समस्या

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थिति लगभग पूरे देश में समान है। यहां इन समुदायों पर शिक्षा के प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता है। बिहार में इन समुदायों पर शिक्षा के प्रभाव को अन्यत्र प्राप्त होने वाले प्रभाव के संकेत के रूप में माना जाना चाहिए। यहां यह बताना जरूरी है कि बिहार राज्य अपनी अनुसूचित जनजातियों के मामले में पिछड़ा हुआ है। लेकिन जहां तक अनुसूचित जातियों की प्रगति की बात है तो इसे भारत का सबसे उन्नत राज्य माना जा सकता है। इस प्रकार बिहार में अनुसूचित जातियों की शिक्षा के पाठ्यक्रम को अपेक्षाकृत उन्नत राज्य की स्थिति के सूचक के रूप में देखा जाना चाहिए, जबकि अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के पाठ्यक्रम को एक ऐसी स्थिति के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए जिसमें आदिवासी काफी पिछड़ा रहता है।

यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए आंदोलन की शुरुआत बिहार राज्य में हुई थी। अछूतों और अन्य निम्न जाति के हिंदुओं के खिलाफ प्रचलित धार्मिक भेदभाव को दूर करने के प्रयास ब्रिटिश शासन से पहले की अवधि में थे, जब मध्यकालीन संत कवियों जैसे। ज्ञानेश्वर, एकनाथ और तुकाराम ने धर्म को असंस्कृत करने और निचली जाति के लिए हिंदू देवताओं की पूजा करने का रास्ता बनाने का प्रयास किया। यह भक्ति मार्ग में चलाया गया एक आंदोलन था और प्राकृत या लोगों की भाषा में भजन और स्लोक की रचना द्वारा निचली जाति के लिए भक्ति या भक्ति की अभिव्यक्ति को संभव बनाने की मांग की गई थी।

आज, बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ अनुसूचित जातियों के नामांकन का प्रतिशत स्कूल के प्रत्येक स्तर (जैसे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और हाई स्कूल) में कुल स्कूल नामांकन के बराबर या यहाँ तक है राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति के प्रतिशत से अधिक है। बिहार उन राज्यों में से एक है जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी है। यद्यपि राज्य में अनुसूचित जातियाँ देश की कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या का केवल 3.8 प्रतिशत हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पर खर्च की गई राशि का लगभग 17% प्राप्त होता है।

लेकिन बिहार राज्य अनुसूचित जनजातियों के मामले में समान रूप से उन्नत नहीं है। खानाबदोश और गैर-अधिसूचित जनजाति अभी भी शैक्षिक प्रगति में कम हैं, वास्तव में, स्वतंत्रता से पहले बहुत से जनजातियों को सुधारने के लिए बहुत कम किया गया था। देश के अन्य भागों की तरह ईसाई मिशनरियों ने दूरस्थ आदिवासी जिलों में शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं को पहुंचाने के लिए कुछ प्रयास किए थे, लेकिन उन्हें बिहार में उस तरह की शानदार सफलता नहीं मिली थी। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में राज्य की अनुसूचित जनजातियों के बीच कुछ प्रमुख आंदोलन हुए हैं। इन दोनों आंदोलनों का जोर आदिवासियों को उनके शोषण के प्रति जागरूक करने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए उनमें साहस, क्षमता और आत्मविश्वास पैदा करने की चेतना जगाने की दिशा में रहा है। इन विशेषताओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ हमें बिहार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा करनी है।

निष्कर्ष

वर्तमान अध्ययन में क्षेत्र विशेष और समूह-विशिष्ट असमानताओं का पता लगाने की दृष्टि से बिहार के गया जिले और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के विकास का वर्णन और विश्लेषण किया गया है। यह केंद्र से परिधि तक लोकल स्टेटस का उन्नयन और सार्वजनिक सुविधाओं, शिक्षा, संचार, परिवहन, उद्योग आदि से संबंधित बुनियादी ढाँचे के विकास के स्तर में जुड़े बदलावों को पिछड़े क्षेत्रों के रूप में उनकी आधिकारिक मान्यता के कारक हैं। हालांकि, इस अध्ययन ने शैक्षिक विकास और इसके व्यापक प्रसार को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करने के लिए क्षेत्र और क्षेत्र-विशिष्ट परिवर्तनों की प्रकृति और सीमा का आकलन करने की कोशिश की। शैक्षिक विकास पर बाधाओं को समझने के लिए वंचित समूहों की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं पर विशेष ध्यान दिया गया था। वर्तमान अध्ययन ने वर्तमान अध्ययन के अनुभवजन्य डेटाबेस के साथ बिहार के गया जिले के जिलों में स्कूली शिक्षा के मौजूदा डेटाबेस को मान्य और बढ़ाने का प्रयास किया। यह विशेष रूप से प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से निवेश के संदर्भ में, इन क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनाई जाने वाली कुछ विशेष रणनीतियों के सुझावों को भी प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। यह लघु/ सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, अनुसूचित जातियों, विशिष्ट शैक्षणिक पिछड़ी जातियों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक पिछड़ेपन के मुद्दों को दूर करने के लिए सरकारी/ गैर-सरकारी/ समुदाय द्वारा आवश्यक हस्तक्षेप (प्रकृति) की प्रकृति का सुझाव देने के लिए विकसित हुआ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

चुध, एस। (2011)। माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉपआउट: दिल्ली के स्लम में रहने वाले बच्चों का एक अध्ययन। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (NUEPA)। समसामयिक पेपर (37)।

अफरीदी, एफ। (2010)। स्कूल की भागीदारी पर स्कूल भोजन का प्रभाव: ग्रामीण भारत से साक्ष्य। भारतीय सांख्यिकी संस्थान चर्चा पत्र, 10-02 <https://ideas.repec.org/p/ind/isipdp/10/.html> पर उपलब्ध

बर्, एच। आर। (1998)। प्राथमिक स्कूल सामाजिक अध्ययन में वैचारिक समझ को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक विकास कार्यक्रम। (अप्रकाशित शोध पत्र), वाइकाटो विश्वविद्यालय।

हर्ड, आर।, कॉनवे, पी।, हिल, एस।, कोएन, वी। और चालॉक्स, टी। (2011)। क्या भारत डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर सकता है? ओईसीडी अर्थशास्त्र विभाग वर्किंग पेपर्स (883)।

कौर, एच। (2010)। आग से बपतिस्मा, धैर्य से जीवित: पंजाब की सीमा बेल्ट में जीवन। वर्किंग पेपर सीरीज़ (3), सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इनक्लूसिव पॉलिसी, अमृतसर: गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी प्रेस।

किंगडन, जी। और भिक्षु, सी। (2010)। स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक उपलब्धि: भारत के नए सबूत। CSAE वर्किंग पेपर, 2010-14।

लवी, वी। (2010)। क्या स्कूल निर्देश समय में अंतर गणित, विज्ञान और पढ़ने में अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि अंतराल की व्याख्या करता है? विकसित और विकासशील देशों से साक्ष्य। NBER वर्किंग पेपर्स, (16227)।

विसारिया, गम्बर, पी। ए। और गोपीनाथ सी। (1993)। भारत में बाल श्रम, पारिवारिक जीवन और प्रजनन क्षमता। वर्किंग पेपर (55), अहमदाबाद: गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च।

राघवेंद्र, पी.एस. और नारायण, के.एस. (2014)। भारत में प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता की समस्याएं और संभावनाएं। शिक्षा में परिप्रेक्ष्य, 20, 144-159।

मित्रा, एस।, रितु, डी। और लेहर, टी। (2018)। शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव का प्रभाव: उत्तर भारतीय स्कूलों का एक केस अध्ययन। ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, 4 (2), 168-180।

सिंह, ए। (2012)। भारतीय बच्चों में प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच की असमानता। जनसंख्या की समीक्षा, 51, 50-68

कुमार, एम। एंड सिंगला, एन। (2013)। भारत में क्षेत्रीय असमानताएँ- पूर्व और बाद के सुधार काल का अध्ययन। मैन एंड डेवलपमेंट, 34 (3), 1-17।

अग्रवाल, टी। (2014)। ग्रामीण और शहरी भारत में शैक्षिक असमानता। शैक्षिक विकास के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 34, 11-19।
Https: // www पर उपलब्ध है।
researchgate.net/publication/259131723_ शिक्षा

यादव, बी.एस. डब्ल्यू। (2018)। हरियाणा में सामाजिक रूप से वंचित प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के बीच पढ़ाई छोड़ने के आकस्मिक कारकों का अध्ययन। (अप्रकाशित पीएचडी थीसिस), कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।

राणा, के। और दास, एस। (2014)। झारखंड में प्राथमिक शिक्षा। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 39 (11), 1171-1178।

राघवन, टी.सी.ए. (2015) है। ग्रामीण भारत में बढ़ती अशिक्षा। द हिंदू (2015, जुलाई, 4)।

चथले, वाई। पी। (2015)। शिक्षा, जनसंख्या और विकास- उत्तर पश्चिमी भारत का एक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य। चंडीगढ़: सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (CRRID)।

Corresponding Author

Ragini Bala*

Research Scholar, School of Education